



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 146]
No. 146]

नई विल्सो, शुक्रवार, जूलाई 25, 1980/शावाण 3, 1902
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 1980/SRAVANA 3, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संलग्न दो जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

गृह संचालन

संकल्प

नई विल्सो, 25 जूलाई, 1980

सं 6-14016/3/80-जी० पी० ए० ४.—जेल प्रशासन में सुधार करने के प्रयत्न पर भारत सरकार का ध्यान जाता रहा है। तदनुसार भारत सरकार ने इस मामले की जांच करने और आवश्यक नियमिती करने के लिए एक समिति गठित करने का संकल्प किया है:—

समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:—

1. न्यायमूलि ए० एन० मूला (सेवानिवृत्त)	प्रध्यक्ष
2. श्री योगेन्द्र शर्मा, सम्बद्ध सदस्य	सदस्य
3. श्रीमती सरोज औरपां, मंसक भवस्य	सदस्य
4. डा० (श्रीमती) एम० लारदा मैनन भूतपूर्व निदेशक, मनोरोग अस्पताल, मद्रास	सदस्य
5. श्री सी० एम० मर्लैया, महानिरीक्षक (जैल), कर्नाटक	सदस्य

6. गृह मंत्रालय के मंथनक सचिव

2. समिति के विनारार्थ निम्नलिखित विषय होंगे:—

- (i) जेल-प्रबन्ध और बंदियों के माध्य व्यवहार की अधिशासित करने वाले कानूनों, नियमों और विनियमों की समीक्षा करना और समाज की सरक्षण पद्धति करने तथा दोषी व्यक्तियों के पुनर्वास के ममग्र उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें करना;
- (ii) बंदियों की मूलभूत आवश्यकताओं के विषेष संबंध में उनके रहन-सहन की दशा की जांच करना और मानव जीवन की गरिमा के अनुरूप मुविधाएं उपनवध करना तथा ऐसे सुधारों के मुकाबले देना जो जल्दी समझे जाएं;

- (iii) हिरासत और सुधार के उद्देश्य के संबंध में जेल कामियों की भर्ती, प्रशिक्षण और विकास को अधिशासित करने वाली नीतियों का मूल्यांकन करना और यह मुनिष्वित करने के उपाय ढूँढ़ना कि अपेक्षित बुद्धिकोशल, अभिभावित और योग्यता वाले व्यक्ति ही जेल सेवा में आएं;
- (iv) जेल सुधारा और सांस्कारिक अनुशासन के मौजूदा स्तर को ऊचा उठाने की दृष्टि से, जेलों के आंतरिक प्रबंध संबंधी कार्यविधि की जांच करना और उपयुक्त परिवर्तनों का सुझाव देना;
- (v) सांस्कारिक व्यवहार, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्योग, कृषि और ऐसी अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के कार्यक्रमों की समीक्षा करना और जेलों का मुद्यारामक केन्द्रों के रूप में विकास करने की दृष्टि से उपाय सुझाना;
- (vi) महिलाओं, किशोरों, बच्चों और मानविक रूप से अस्वस्य व्यक्तियों के प्रति विशिष्ट व्यवहार के लिए उपाय सुझाना;
- (vii) खली जेलों के कार्य की समीक्षा करना और उनमें सुधार के बास्ते उपाय सुझाना;
- (viii) कारायाम की सजा में मापी देने, पेरोल और परिवीक्षा की प्रणाली की जांच-पड़ताल करना और इस दृष्टिकोण में एक-रूपता लाने तथा इनका मानकीकरण करने के बास्ते मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करना;
- (ix) जेल शामन से मंबधित कोई अन्य मामला, जिस पर समिति विचार करना चाहे।

3. जब कभी प्रावधारक हों, समिति को सरस्य सहयोगित करने की शक्ति होगी ।
4. समिति अपनी रिपोर्ट छह महीने की प्रवधि के भीतर प्रस्तुत करेगी और विशिष्ट विषयों पर अंतरिम रिपोर्टें तैयार होने ही प्रस्तुत करेगी । तिहाड़ जेल के संबंध में, समिति को अपनी सिफारिशें एक महीने के भीतर देनी होंगी ।
5. समिति का मुख्यालय दिल्ली में होगा ।

6. समिति अपने कार्यों के निरापादन की अपनी कार्यविधि स्वयं निश्चिरित करेगी । भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग समिति को ऐसी सूचना और वस्तावेज भेजेंगे और ऐसी सहायता उपलब्ध कराएंगे जिसकी उमे प्रावधारकता होंगी । भारत सरकार का यह विषयास है कि राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन तथा संबंधित अन्य समिति को अपना पूरा-पूरा सहयोग और महायता प्रदान करेंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजी जाए ।

- (i) समिति के अध्यक्ष और सदस्यगण
- (ii) संसदीय कार्य विभाग
- (iii) भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग
- (iv) सभी राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन ।

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

श्रीवल्लभ शरण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RESOLUTION

New Delhi, the 25th July, 1980

No. VI 14016/3/80-GPA. IV.—The question of effecting improvement in prison administration has been engaging the attention of the Government of India. Government of India have accordingly resolved to set up a Committee to enquire into the matter and to make necessary recommendations.

The Committee shall consist of :—

1. Justice A. N. Mulla (Retd.)	Chairman
2. Shri Yogendra Sharma, M.P.	Member
3. Smt. Saroj Kharapade, M.P.	Member
4. Dr. (Mrs.) M. Sarada Menon, former Director, Mental Hospital, Madras	Member
5. Shri C. S. Malliah, I.G. (Prisons), Karnataka	Member
6. Joint Secretary in the Ministry of Home Affairs	Member

2. The following will be the terms of reference of the Committee :—

- (i) to review the laws, rules and regulations governing the management of prisons and the treatment of prisoners and to make recommendations keeping in view the overall objective of protecting the society and rehabilitating the offenders;

- (ii) to examine the living conditions of prisoners with specific reference to their basic needs and provision of facilities compatible with the dignity of human life and to suggest improvements as considered necessary;
- (iii) to reappraise the policies governing the recruitment, training and development of prison personnel in relation to the objective of custody and correction and to find ways of ensuring that persons with requisite talent, aptitude and ability man the prison service;
- (iv) to look into the procedure regarding the internal management of prisons with a view to raising the present level of prison security and institutional discipline and to suggest appropriate change;
- (v) to review the programmes of institutional treatment, education, vocational training, industry, agriculture and such other occupational activities and to suggest measures with a view to develop prisons as correctional centres;
- (vi) to suggest measures for the specialised treatment of women, adolescents, children and mentally sick persons;
- (vii) to review the working of open-air prisons and to suggest measures for improvement;
- (viii) to scrutinise the system of remission of prison sentence, parole and probation and to lay down guidelines for bringing about uniformity and standardisation in approach;
- (ix) any other matter relating to prison administration that the Committee may like to consider.

3. The Committee will have power to co-opt members as and when necessary.

4. The Committee will submit its report within a period of six months and submit interim reports on specific subjects as and when these are ready. It shall make its recommendations with regard to Tihar Jail within a month.

5. The Headquarters of the Committee will be at Delhi.

6. The Committee will devise its own procedure in the discharge of its functions. All the Ministries and Departments of the Government of India will furnish such information and documents and provide such assistance as may be required by the Committee. The Government of India trusts that the State Governments and Union Territory Administrations and others concerned will extend their fullest cooperation and assistance to the Committee.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to :—

- (i) Chairman and Members of the Committee
- (ii) Department of Parliamentary Affairs
- (iii) All Ministries and Departments of the Government of India
- (iv) All State Governments and Union Territory Administrations.

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. V. SHARAN, Jt. Secy.